माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण,

1. हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा के पंचम तथा वर्ष 2019 के प्रथम सत्र के शुभारम्भ पर मैं सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ। मैं इस सम्माननीय सदन के सभी सदस्यों तथा आपके माध्यम से, हिमाचल प्रदेश की जनता को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह नववर्ष हम सभी को प्रदेशवासियों की सेवा करने के लिए शक्ति तथा प्रतिबद्धता प्रदान करेगा।

2. गत वर्ष मेरी सरकार के गठन पर प्रदेश को मुख्य मंत्री के रूप में युवा नेतृत्व प्राप्त हुआ। इस नेतृत्व ने नई ऊर्जा एवं दूरदर्शिता के साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना आरम्भ किया। प्रदेश के प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में जा कर लोगों से सीधे सम्पर्क किया एवं उनकी समस्याओं का प्रभावी ढंग से निवारण किया।

3. मुझे खुशी है कि मेरी सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास' के मूलमंत्र को आधार बनाते हुए, गत एक वर्ष में सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों का पुनर्निर्धारण किया है। यह गौरव का विषय है कि मेरी सरकार ने 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः' के आदर्श को अपनाते हुए अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही अधिकतर

चुनावी वायदों को प्रभावी ढंग से पूरा किया है। इन सभी कार्यक्रमों और योजनाओं की उपलब्धियों का उल्लेख इस प्रकार से है।

4. राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2018–19 के लिए सभी अधिसूचित खरीफ और रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की लागत का कम से कम 150 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ा दिया है। सरकार की इस पहल से किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिली है। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार ने प्रदेश में खेती को एक नई दिशा प्रदान की है। चालू वित्त वर्ष में राज्य में एक नई योजना 'प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान' शुरू की गई। इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष लगभग 9 हज़ार किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया गया है। अब तक लगभग 3 हजार कृषकों द्वारा इस पद्धति को सफलतापूर्वक अपनाया गया है।

5. मिट्टी के पोषक तत्वों का सही और सन्तुलित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' के अन्तर्गत सभी कृषकों को ऑनलाइन मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वर्ष 2018–19 में 4 लाख 80 हजार ऐसे कार्ड बनाए गए हैं। किसानों की फसलों को बंदरों, जंगली जानवरों एवं बेसहारा पशुओं से बचाने के लिए 'मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना' के अन्तर्गत सौर बाड़ पर अनुदान बढ़ाया गया है। इस योजना के

अन्तर्गत अब तक किसानों को 22 करोड़ रूपये का अनुदान दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018–19 में 1 लाख 25 हजार कृषकों को 'प्रधान मन्त्री फसल बीमा योजना' के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

6. हिमाचल प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बागवानी का महत्त्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2018–19 में लगभग 2 हज़ार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र बागवानी के अन्तर्गत लाया गया है। राज्य में बागवानी के समग्र विकास में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं जैसे 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन', 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' तथा 'प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना' महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। चालू वित्त वर्ष में इन योजनाओं के अन्तर्गत उच्च मूल्य के फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती के लिए 35 हजार 500 वर्ग मीटर क्षेत्र पॉलीहाउस व ग्रीनहाउस, 5 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र छायादार जाली गृह तथा 2 हज़ार वर्ग मीटर क्षेत्र प्लास्टिक–टनल के अन्तर्गत लाया गया है।

7. मेरी सरकार ने पुष्प खेती के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु चालू वित्त वर्ष में 'हिमाचल पुष्प क्रान्ति योजना' आरम्भ की है। इस योजना में 25 हजार 268 वर्ग मीटर क्षेत्र पॉलीहाउस के अन्तर्गत लाया जाएगा। इसी प्रकार, मेरी सरकार ने 'मुख्य मन्त्री मधु विकास योजना' भी आरम्भ की है। इस

योजना के अन्तर्गत मौन पालकों को मौन वंश, मौन गृहों एवं मौन उपकरणों के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है।

8. बागवानी के क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए 'मौसम आधारित फसल बीमा योजना' के अन्तर्गत 1 लाख 62 हज़ार बागवानों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 95 लाख 86 हज़ार बीमित फल पौधों पर प्रदेश सरकार द्वारा 18 करोड़ 86 लाख रूपये की राशि प्रीमियम अनुदान के रूप में वहन की गई है। इसके अतिरिक्त किसानों एवं बागवानों को लागत कम करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कर अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत सेब, अन्य फलों एवं सब्जियों को कर मुक्त कर दिया है। जून, 2018 से हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में फूलों की ढुलाई की दरों में 20 प्रतिशत की कमी की गई है।

9. किसानों की आर्थिकी के उत्थान हेतु प्रदेश सरकार ने सहकारिता के अन्तर्गत की जा रही गतिविधियों को भी नई दिशा प्रदान की है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 163 करोड़ रूपये लागत की एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं सोलन व मण्डी जिलों में शुरू की गई हैं जिससे इन जिलों में सहकारी आन्दोलन सुदृढ़ होगा।

10. किसानों की आर्थिकी में पशुधन का भी महत्त्वपूर्ण योगदान है। मेरी सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 में प्रदेश में 8 पशु औषधालयों को स्तरोन्नत करके पशु चिकित्सालय बनाया गया और 2 नए पशु औषधालय भी खोले गए। अनुसूचित जाति तथा अन्य वर्ग के किसानों द्वारा पाली जा रही देसी नस्ल की गायों को गर्भावस्था के दौरान 50 प्रतिशत उपदान पर चारा उपलब्ध करवाने के लिए 4 करोड़ 60 लाख रूपये खर्च किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा 'दुग्ध उद्यमी विकास योजना' के लाभार्थियों को देसी नस्ल की गाय खरीदने पर 20 प्रतिशत व अन्य नस्लों की गाय खरीदने पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त उपदान प्रदान किया जा रहा है।

11. मेरी सरकार ने प्रदेश में 'गौसेवा आयोग' गठित करने के लिए शीतकालीन विधान सभा सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 पारित कर दिया है। इस आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में गाय के संरक्षण, कल्याण और इनकी स्वदेशी नस्लों के संवर्धन के लिए नीतियां व कार्य योजना तैयार करना होगा। प्रदेश में बेसहारा गौवंश को आश्रय प्रदान करने के लिए गौ–अभ्यारण्यों व जिला स्तरीय बड़े गौसदनों की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार ने गौसदनों एवं गौशालाओं की वित्तीय सहायता के लिए मन्दिर न्यासों की कुल आय का 15 प्रतिशत भाग देने का महत्वपूर्ण निणर्य लिया है।

12. किसानों की आर्थिकी सुधारने हेतु मेरी सरकार द्वारा 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारन्टी योजना' के कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों में जल संरक्षण व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्रोत्साहन देना, मज़दूरी एवं सामग्री के 60:40 के अनुपात को जिला स्तर पर आंकना, 100 दिनों के कार्य दिवस को 120 करना व प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही 10 प्रतिशत हिस्सेदारी को पहले ही जारी करना आदि शामिल हैं। इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष में दिसम्बर, 2018 तक 660 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं। इस वर्ष, अब तक 4 लाख 93 हज़ार 148 परिवारों ने 220 लाख कार्य दिवस अर्जित किए हैं, जिसके अन्तर्गत 33 हजार 757 परिवारों ने 120 दिन के कार्य दिवस पूर्ण कर लिए हैं। इस योजना के अन्तर्गत अर्जित कार्य दिवस में से 63 प्रतिशत कार्य दिवस महिलाओं द्वारा अर्जित किए गए हैं।

13. चालू वित्त वर्ष में मनरेगा के अन्तर्गत 15 हज़ार 873 भूमि सुधार से सम्बन्धित कार्य किए गए जिससे किसानों की आमदनी में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, 10 हज़ार टैंकों का निर्माण किया गया है, जिनकी क्षमता 8 करोड़ लीटर है। किसानों के कृषि उत्पाद को मंडियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना के अन्तर्गत लगभग 308 किलोमीटर ग्रामीण रास्तों का निर्माण हुआ है।

14. वर्ष 2018–19 में 2 हज़ार 691 सक्रिय जलाशय मछुआरों को दो माह बन्द सीजन के दौरान दी जाने वाली सहायता को 1 हज़ार 800 रूपये से बढ़ाकर 3 हज़ार रूपये किया गया है। किसानों को आय के अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए मेरी सरकार द्वारा 'नील क्रान्ति योजना' के अन्तर्गत 2 करोड़ 28 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करके 100 नई ट्राऊट इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है।

15. मेरी सरकार ने जनता से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करने हेतु एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम 'जनमंच' आरम्भ किया है। जनवरी, 2019 तक 63 विधान सभा क्षेत्रों में 96 जनमंच कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 24 हज़ार 424 मांगपत्र एवं शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल जनता की समस्याओं का निपटारा किया गया है बल्कि 246 स्वास्थ्य कैम्प भी लगाए गए, जिनमें 38 हज़ार 178 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त 4 हज़ार 578 इंतकाल निपटाए गए, 743 योजनाओं का निरीक्षण किया गया, 28 हज़ार 225 विभिन्न प्रमाण–पत्र जारी किए गए, 19 हज़ार 300 लाभार्थियों से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कागज़ात पूर्ण करवाए गए, 436 ग्राम पंचायतों तथा 121 अन्य स्थानों पर सफाई अभियान चलाया गया। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 लाख 74 हज़ार

डिजिटल राशन कार्ड जारी किए गए व 1 लाख 42 हज़ार लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए।

16. मेरी सरकार ने नागरिकों को पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन व भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा अनेक प्रणालियों को लागू किया जिसमें समग्र समाधान, हिम प्रगति, जनमंच, रोज़गार सृजन, सहकारिता के ऑनलाईन आवेदन, प्रदेश व सभी ज़िलों की वेबसाइट का देश भर में सबसे पहले नवीनीकरण उल्लेखनीय हैं। मानव सम्पदा, ई–विधान व मिड–डे मील के सॉफ्टवेयर का देश के अन्य राज्यों में भी अनुकरण किया गया जोकि प्रशंसनीय है। हिमाचल प्रदेश देश भर में अपने नागरिकों को 'ई–बजट', 'एमहिमभूमि', 'सर्किल रेट्स', 'शक्ति महिला सुरक्षा' व 'शोर नहीं' जैसी मोबाईल ऐप्पस सुविधाएं प्रदान करने वाला अग्रणी राज्य बना है। यह इन्हीं प्रयासों का प्रतिफल है कि चालू वित्त वर्ष में मानव सम्पदा व ई–विधान को राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस और वेब–पोर्टल को वेब–रत्न पुरस्कार से प्रदेश को सम्मानित किया गया है।

17. सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य के लोगों के साथ जुड़ने के लिए, मेरी सरकार ने मुख्य मंत्री आई0टी0 प्रकोष्ठ की स्थापना की है। सरकारी विभागों की कार्यकुशलता एवं जवाबदेही बढ़ाने और पेपर रहित वातावरण बनाने के लिए वर्ष 2018 में 19 कार्यालयों में ई–ऑफिस प्रारम्भ किया गया है जिसके माध्यम से 6

हजार 953 फाइलें ऑनलाईन चल रही है। प्रदेश के 6 विकास खण्डों की 221 ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा प्रदान की गई है।

18. मेरी सरकार द्वारा 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर योजना' के तहत 3 हज़ार 175 करोड़ रूपये 56 योजनाओं के लाभार्थियों के आधार–सक्षम बैंक खातों में सफलतापूर्वक हस्तान्तरित किए गए हैं।

19. मेरी सरकार द्वारा 'एकल खिड़की प्रणाली' के अंतर्गत निवेषकों की सुविधा के लिए एक 'सिंगल प्वाइंट कॉन्टैक्ट' की सुविधा विकसित की गई है, जिसके अंतर्गत 10 संबंधित विभागों की 37 सेवाओं को जोड़ा गया है। अब निवेशक ऑनलाईन सांझा आवेदन पत्र द्वारा बिना किसी दखल के अपनी परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सभी सम्बन्धित विभागों की स्वीकृतियां प्राप्त कर सकते हैं।

20. मेरी सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों में प्रशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। पंचायतों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और लेखों के सही रख–रखाव के लिए 'प्रिया सॉफ्ट' सॉफ्टवेयर में सभी पंचायतों के खातों का रख–रखाव किया जा रहा है। प्रथम अप्रैल, 2018 से परिवार रजिस्टर ऑनलाइन कर दिए गए हैं।

21. मेरी सरकार द्वारा 'डिजिटल इण्डिया भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम' के अन्तर्गत जिला कांगड़ा, बिलासपुर, चम्बा, किन्नौर, हमीरपुर, लाहौल–स्पीति व मण्डी की मुसाबियों के डिजिटलीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अब इन्हें जमाबंदियों के साथ एकीकृत करके राजस्व विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। आम जनता अपने जमाबंदी के डाटा को मुसाबियों सहित डाउनलोड कर सकती है।

22. कुल्लू, चम्बा और लाहौल–स्पीति जिलों में 23 और 24 सितम्बर, 2018 को भारी वर्षा और बर्फबारी के कारण कई पर्यटक लाहौल–स्पीति जिले में फंस गए थे। ऐसी चिन्ताजनक स्थिति में मेरी सरकार ने तुरन्त कार्रवाई करके भारतीय वायु सेना के 7 हेलिकॉप्टरों द्वारा 252 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके अतिरिक्त, 2 हज़ार 509 लोगों को रोहतांग सुरंग के सड़क मार्ग से निकाला गया। इस अवधि के दौरान 1 हज़ार 272 छात्रों, शिक्षकों और अन्य व्यक्तियों को जिला चम्बा के होली तहसील से भी बचाया गया। इसके अतिरिक्त, कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल क्षेत्र से 120 व्यक्तियों, लगभग 20 हजार भेड़–बकरियों और 350 घोड़ों को भी बचाया गया, जो बेमौसमी बर्फबारी के कारण वहां फंस गए थे। मेरी सरकार इस अभियान को सफल बनाने और फंसे हुए लोगों की जान बचाने में सहयोग प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र

मोदी जी का विशेष आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने इस सारे अभियान में व्यक्तिगत रूचि दिखाई।

23. मेरी सरकार नशे के सेवन को रोकने के प्रति कृतसंकल्प है। इस दिशा में राज्य स्तर पर बड़ा अभियान आरम्भ किया गया है। वर्ष 2018 के दौरान, स्वापक औषधी एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत 1 हज़ार 342 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 10 विदेशी नागरिकों सहित 1 हज़ार 724 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भांग और अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए नियमित अभियान चलाए जा रहे हैं। थाना स्तर पर ड्रग रोकथाम समितियों की स्थापना की गई है। ट्विटर और फेसबुक सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मशहूर हस्तियों के माध्यम से विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि नशीली दवाओं के विरूद्ध युवाओं में जागरूकता पैदा की जा सके।

24. मुझे खुशी है कि मेरी सरकार द्वारा इस कुरीति को पूर्णतः समाप्त करने के लिए इस अभियान में पड़ोसी राज्यों को शामिल कर इन राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के साथ व पुलिस महानिदेशकों के स्तर पर समन्वय स्थापित किया गया है। इसी उद्देश्य से हिमाचल के मुख्य मंत्री की पहल पर हरियाणा, पंजाब व उत्तराखंड के मुख्य मन्त्रियों तथा राजस्थान, दिल्ली व चण्डीगढ़ के उच्च अधिकारियों का एक क्षेत्रीय सम्मेलन पंचकूला में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन

के दौरान खुफिया जानकारी सांझा करने और ड्रग माफिया के विरूद्व संयुक्त रणनीति बनाने तथा इसे लागू करने के लिए एक संयुक्त सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

25. मेरी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए 'गुडिय़ा हेल्पलाइन' और 'शक्ति बटन मोबाइल ऐप' शुरू किए हैं। गुड़िया हेल्पलाइन के माध्यम से जनवरी, 2018 से अब तक 1 हज़ार 398 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 1 हज़ार 344 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। चालू वित्त वर्ष में ईव–टीज़र और अन्य असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए लड़कियों को सशक्त बनाने और उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए, राज्य की सरकारी पाठशालाओं में छात्राओं को 'आत्म रक्षा' तथा 'समग्र शिक्षा अभियान' के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 1 हजार 68 स्कूलों में लगभग 54 हजार छात्राओं को राज्य पुलिस द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में जिला सोलन, हमीरपुर और चंबा में 3 महिला पुलिस थानों की स्थापना भी की गई है।

26. मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने तथा वन माफिया, खनन माफिया और ड्रग माफिया से कड़ाई से निपटने के लिए 'होशियार सिंह हेल्पलाइन–1090' भी आरम्भ की गई है। कोई भी व्यक्ति इस 'टोल फ्री' नम्बर पर अवैध वन कटान, नशा अथवा

खनन गतिविधियों के सम्बन्ध में सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाती है। इस हेल्पलाइन पर जनवरी, 2018 से अब तक 1 हज़ार 325 शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा इन सभी पर त्वरित कार्रवाई की गई है।

27. मेरी सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। खनिज उत्पादों के अवैध खनन को रोकने तथा आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न नदी–नालों में रेत, बजरी व पत्थर की 121 खानों को खुली बोली के माध्यम से नीलाम किया गया है। इससे रॉयलटी के रूप में 405 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त होगी।

28. मेरी सरकार ने सड़कों के निर्माण व रख–रखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। प्रदेश सरकार के प्रयत्नों से भारत सरकार ने मार्च, 2018 तक 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के अन्तर्गत 120 सड़कों और 4 पुलों के निर्माण के लिए 385 करोड़ रूपये तथा दिसम्बर, 2018 तक 219 सड़कों और 9 पुलों के निर्माण के लिए 843 करोड़ रूपये स्वीकृत किए हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने सड़कों एवं पुलों के निर्माण में तेजी लाने के लिए 1 हज़ार 359 विधायक प्राथमिकताओं के कार्यों के लिए 3 हज़ार 676 करोड़ रूपये स्वीकृत किए हैं। नवम्बर, 2018 तक 948 परियोजनाओं को पूरा कर दिया गया है।

29. मेरी सरकार ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग 70 (नया राष्ट्रीय उच्च मार्ग–3) हमीरपुर से मण्डी के भाग जिसकी लम्बाई 124 कि0मी0 है और राष्ट्रीय उच्च मार्ग 72बी (नया राष्ट्रीय उच्च मार्ग–707) पाँवटा साहिब से गुम्मा के भाग जिसकी लम्बाई 97 कि0मी0 है, के डबल लेन उन्नयन के लिए 3 हज़ार करोड़ रूपए का प्राक्कलन विश्व बैंक से वित्तीय सहायता के लिए केन्द्र सरकार को भेज दिया है।

30. मेरी सरकार 'जल ही जीवन है' के सिद्धान्त को आधार बनाते हुए, प्रदेश की जनता को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु वचनबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 500 बस्तियों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर की दर से पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। नवम्बर, 2018 तक 289 बस्तियों को यह सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है।

31. प्रतिकूल मौसम के कारण गत वर्ष गर्मियों में आए पेयजल संकट का मेरी सरकार ने कुशल प्रबन्धन से सफलतापूर्वक निदान किया। विशेषकर शिमला शहर में स्थिति अधिक गम्भीर होने के कारण, सरकार द्वारा दो महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिनमें चाबा नामक स्थान से सतलुज नदी से 10 एम0एल0डी0 अतिरिक्त जल उपलब्ध करवाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त शिमला पेयजल आपूर्ति योजना के गिरी स्रोत में जल की स्थिरता बनाए रखने के लिए बांध निर्माण का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के

सूखाग्रस्त एवं पेयजल की कमी वाले क्षेत्रों में इस वित्तीय वर्ष में अब तक 1 हजार 594 अतिरिक्त हैण्डपम्पों की स्थापना की गई है।

32. विश्व बैंक ने दिनांक 16 जनवरी, 2019 को 986 करोड़ रूपये की शिमला जलापूर्ति और सीवरेज परियोजना को अपनी स्वीकृति प्रदान की और पहली किश्त के रूप में 292 करोड़ रूपये जारी करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की। शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड ने पानी के रिसाव को रोकने के लिए 14 किलोमीटर की मुख्य जलापूर्ति लाईन को बदल दिया है जिससे शिमला में पानी की आपूर्ति 40 एम0एल0डी0 से बढ़कर 51 एम0एल0डी0 हो गई है। इस प्रक्रिया में पानी का रिसाव 27 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत से कम रह गया है। क्रैगनैनों से ढली तक 7.5 किलोमीटर, अश्वनी खड्ड से कसुम्पटी तक 4.5 किलोमीटर और संजौली से रिज भण्डारण टैंक तक 2 किलोमीटर लम्बी मुख्य जलापूर्ति लाईनों को बदल दिया गया है।

33. मेरी सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत नवम्बर, 2018 तक 1 हज़ार 880 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त मध्यम सिंचाई परियोजना नादौन के निर्माण कार्य को गति प्रदान करने हेतु 42 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई है। जिससे इस योजना के दायें तट के कार्य को जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा।

34. मेरी सरकार ने चालू वित्त वर्ष में दिसम्बर, 2018 तक 1 हज़ार 765 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, जोकि उपरोक्त वित्त वर्ष के लिए तय किए गए लक्ष्य का 91 प्रतिशत है। चालू वित्त वर्ष में विभिन्न उपभोक्ता परिसरों में 20 हज़ार 520 पुराने विद्युत मीटरों के स्थान पर नए इलैक्ट्रोनिक मीटर तथा विभिन्न एच0टी0 व एल0टी0 लाईनों में मौजूद लकड़ी के 4 हज़ार 325 पुराने खम्भों के स्थान पर नए लोहे के खम्भें लगाए गए हैं।

35. मेरी सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष के दौरान 873 किलोवाट उच्च क्षमता के ग्रिड संचालित रूफ टॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। इसे और अधिक गति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार ने अतिरिक्त रूप से 10 प्रतिशत या 4 हज़ार रूपये प्रति किलोवाट राज्य अनुदान घरेलू उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाने हेतु स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त 139 किलोवाट उच्च क्षमता के ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र, 5 हज़ार 953 सौर स्ट्रीट लाइटें, 5 हज़ार लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर जल तापीय संयंत्र तथा 3.50 मैगावाट क्षमता की एक लघु जल विद्युत परियोजना प्रदेश में स्थापित की हैं।

36. चालू वित्त वर्ष के दौरान कालका–शिमला रेल लाईन पर भारत सरकार द्वारा पारदर्शी कोचिज़ (विस्टाडोम) चलाई गई है। इससे प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी तथा

प्रदेश के प्राकृतिक सौन्दर्य को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। इसके अतिरिक्त नंगल डैम–तलवाड़ा रेल लाईन का निर्माण कार्य अम्ब इन्दौरा से दौलतपुर चौक तक पूर्ण कर यातायात के लिए जनवरी, 2019 में खोल दिया गया है। इस रेल लाईन को दौलतपुर चौक तक बढ़ाने से पर्यटकों को चिन्तपूर्णी, ज्वालाजी एवं अन्य पर्यटक स्थलों पर पहुँचने में सुविधा होगी।

37. भानुपली–बिलासपुर–बेरी रेल लाईन के 20 किलोमीटर के प्रथम चरण के लिए मेरी सरकार ने सम्पूर्ण 25.21 हेक्टेयर भूमि अर्जित करने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है तथा शेष भू–अर्जन कार्य प्रगति पर है। नंगल डैम–तलवाड़ा रेल लाईन के लिए राज्य में पड़ने वाली भूमि को अर्जित किया जा चुका है और अब इस भूमि को रेलवे के नाम हस्तान्तरण हेतु रजिस्ट्री एवं इन्तकाल का कार्य प्रगति पर है।

38. राज्य में तीव्र तथा संतुलित औद्योगिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता के दृष्टिगत मेरी सरकार के कार्यकाल में 113 परियोजनाओं को 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस और मानिटरिंग अथॉरिटी' द्वारा मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं में 3 हज़ार 622 करोड़ का निवेश होगा और इनमें 7 हज़ार 655 लोगों के लिए रोज़गार सृजन का अनुमान है।

39. मेरी सरकार ने ऑनलाईन मॉनीटरिंग सिस्टम 'हिमप्रगति' प्रारम्भ की है जिसमें बहुउद्देशीय पनबिजली, औद्योगिक, पर्यटन तथा अन्य संरचनात्मक परियोजनाओं के शीघ्र निपटारे एवं अनुमोदन के लिए मुख्य मंत्री द्वारा मॉनीटरिंग की जा रही है। इस प्रणाली के अन्तर्गत अभी तक 10 हज़ार 202 करोड़ रूपये अनुमानित लागत वाली 79 परियोजनाओं की मॉनीटरिंग की जा रही है।

40. मेरी सरकार ने 'राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन' के तहत 30 उद्यमियों को 10 करोड़ रूपये मंजूर किए हैं। मेरी सरकार ने राज्य में युवाओं में उद्यमिता विकास व स्वरोज़गार सृजन के लिए 'मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना' आरम्भ की है। राज्य में 'स्टार्टअप योजना' लागू की गई है। इस योजना के तहत राज्य में 8 केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें 40 स्टार्ट–अप पंजीकृत हुए हैं तथा इनमें से 6 स्टार्ट–अप परियोजनाएं शुरू कर दी गई हैं। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश 'स्टार्ट–अप इको सिस्टम' को 'हिल स्टेट लीडर' और 'एस्पायरिंग लीडर' के रूप में मान्यता दी है। भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को स्टार्ट–अप योजना के कार्यान्वयन के लिए 'Regulator Change Champion' का दर्जा दिया गया है।

41. मेरी सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण तथा अनछुए स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने तथा युवाओं को स्वरोज़गार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 'नई राहें, नई मंजिलें' नामक योजना

आरम्भ की है। इस योजना के प्रथम चरण में 50 करोड़ रूपये से जंजैहली, जिला मण्डी में ईको टूरिज्म परियोजना, बीड़–बिलिंग, जिला कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग डैस्टिनेशन, चांशल, जिला शिमला में स्की डैस्टिनेशन, लारजी जलाशय, जिला कुल्लू तथा पौंग बांध, जिला कांगड़ा में पर्यटन परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्तमान में ज़िला शिमला के बनरेडू, संजौली–ढली बाई पास, ज़िला चम्बा के चुवाड़ी व कुन्दी, ज़िला कुल्लू के खोशाला वशिष्ठ, ज़िला मण्ड़ी के कुन्नु, नाचन, ढीम–कटारू व कांगनीधार एवं ज़िला लाहौल–स्पीति के गोम्पा में नये हैलीपोर्ट व हैलीपैड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के हवाई–अड्डे की स्थापना के लिए मण्डी के नागचला में स्थान चिन्हित किया गया है।

42. मेरी सरकार द्वारा बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पैंशन के लिए आयु 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने के फलस्वरूप 1 लाख 60 हज़ार पात्र व्यक्तियों को प्रत्यक्ष लाभ हुआ है। इससे 70 वर्ष से अधिक 60 हज़ार नए व्यक्ति पैंशन के लिए पात्र हुए हैं व 70 वर्ष से 80 वर्ष के बीच 1 लाख व्यक्ति जो कि पहले से पैंशन ले रहे थे, की पैंशन में बढ़ौतरी हुई है। इसके अतिरिक्त, अन्य श्रेणियों के 37 हज़ार 139 पात्र व्यक्तियों को पैंशन प्रदान की जा रही है। चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा 5 लाख 11 हज़ार व्यक्तियों को

सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान करने हेतु 600 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जा रही है।

43. मेरी सरकार महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। चालू वित्त वर्ष में 'मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना' के अन्तर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 4 हज़ार रूपये से बढ़ाकर 5 हज़ार रूपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 'बेटी है अनमोल योजना' के तहत बी0पी0एल0 परिवारों की लड़कियों के लिए जन्म उपरान्त दिए जाने वाले अनुदान को 10 हज़ार से बढ़ाकर 12 हज़ार रूपये कर दिया गया है। इससे 21 हज़ार 483 लोग लाभान्वित हुए हैं।

44. मेरी सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सक्षम गुड़िया बोर्ड का गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं व किशोरियों के सशक्तिकरण नीति के लिए उनकी सुरक्षा से सम्बन्धित अधिनियमों, नियमों, नीतियों और कार्यक्रमों पर सिफारिश करना, बालिकाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और बालिकाओं व किशोरियों के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने हेतु सुझाव देना है।

45. 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' के अन्तर्गत भारत सरकार ने 147 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश को

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया है। प्रदेष ने 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' को सफलतापूर्वक लागू करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

46. मेरी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व अन्य पिछड़ा वर्गों को गृह निर्माण के अन्तर्गत नए मकान बनाने के लिए 1 लाख 30 हज़ार रुपये प्रति लाभार्थी तथा मकान मुरम्मत के लिए 25 हज़ार रूपये प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान राशि प्रदान कर रही है। वर्तमान वित्त वर्ष में 1 हज़ार 412 मकान बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 18 करोड़ 36 लाख रुपये की राशि व्यय की जा रही है।

47. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत निम्न एवं मध्यम आय वर्गीय परिवारों को नए आवासों के निर्माण हेतु वर्तमान वित्त वर्ष में 21 करोड़ 87 लाख रूपये की राशि जारी की गई है तथा 3 हज़ार 158 आवासों के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अन्य 777 आवासों का कार्य प्रगति पर है। सितम्बर, 2018 में प्रदेश को इस योजना के अन्तर्गत श्रेष्ठ कार्य करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है। इसके अतिरिक्त 'मुख्य मंत्री आवास योजना' के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 के दौरान 42 करोड़ रूपये की लागत से 3 हज़ार 14 आवासों का निर्माण किया जा रहा है।

48. मेरी सरकार ने प्रदेश के पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों, सैनिक विधवाओं, युद्ध विधवाओं, शौर्य पुरस्कार विजेताओं व उनके आश्रितों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं की बुढ़ापा पैंशन 500 रूपये प्रति माह से बढ़ा कर 3 हज़ार रूपये प्रति माह कर दी गई है। पूर्व सैनिकों तथा सैनिक विधवाओं के बच्चों को विशेष निधि से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आय सीमा 3 लाख रूपये से बढ़ाकर 7 लाख रूपये प्रतिवर्ष की गई है। मेरी सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 60 वर्ष या अधिक आयु के 1 हजार 682 भूतपूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं जो किसी प्रकार की पैन्षन नहीं ले रहे हैं, 934 शौर्य पुरस्कार विजेताओं, युद्ध में शहीद व अपंग हुए सैनिकों के 35 आश्रितों, 54 पात्र नॉन पैन्शनर पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं को 10 करोड़ 55 लाख रूपये की राशि वितरित की है। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों के राहत एवं पुनर्वास हेतु 60 लाख रूपये की धनराशि वितरित की है।

49. मेरी सरकार ने इस वित्त वर्ष में दालों की खरीद बफर स्टॉक्स के माध्यम से करने का निर्णय लिया है जिसके कारण खर्च में बचत हुई। राशनकार्ड धारकों को विशेष अनुदानित योजना के अन्तर्गत 1 किलो दाल चना अतिरिक्त तौर पर उपलब्ध करवाई जा रही है। दालों की खरीद पर पारदर्शिता लाने के कारण फरवरी, 2018 से अक्तूबर, 2018 तक 51 करोड़ 73 लाख रूपये की बचत हुई है।

इसके अतिरिक्त चीनी का क्रय हरियाणा राज्य की सहकारी चीनी मिलों से किया जा रहा है, जिससे प्रदेश सरकार को माह फरवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक कुल 37 करोड़ 45 लाख रूपये की बचत हुई है। इस प्रकार मेरी सरकार ने चालू वित्त वर्ष में दालों एवं चीनी के क्रय पर कुल 89 करोड़ 18 लाख रूपये की बचत की है। इस बचत के कारण सभी राशनकार्ड धारकों के लिए चीनी का मूल्य 5 रूपये प्रति किलो कम किया गया।

50. भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वाकांक्षी 'उज्जवला योजना' प्रारम्भ की है जिसमें गृहिणियों को गैस कनैक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अब तक इस योजना के अन्तर्गत 86 हज़ार कनैक्शन जारी किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में मेरी सरकार ने प्रदेश में 'गृहिणी सुविधा योजना' प्रारम्भ की है जिससे प्रदेश की सभी पात्र गृहिणियों को पूर्णतः मुफ्त गैस कनैक्शन जारी किए जा रहे हैं। 31 जनवरी, 2019 तक कुल 40 हज़ार परिवारों को मुफ्त में गैस कनैक्शन जारी किए जा चुके हैं तथा यह प्रक्रिया तब तक निरन्तर जारी रहेगी, जब तक कि सभी पात्र परिवारों को गैस कनैक्शन नहीं मिल जाते।

51. मेरी सरकार अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिए वचनबद्ध है। चालू वित्त वर्ष में जनजातीय उप योजना के अन्तर्गत विभिन्न अनुसूचित

जनजातीय क्षेत्रों में 567 करोड़ रूपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्त वर्ष में भारत सरकार ने विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्रदेश को 43 करोड़ रूपये जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त 67 करोड़ 70 लाख रूपये की अतिरिक्त धनराशि का अनुमोदन भी प्रदान किया। यह धनराशि भारत सरकार द्वारा आज तक के किसी भी वित्तीय वर्ष में अनुमोदित की गई अतिरिक्त राशि की तुलना में सबसे अधिक है। प्रदेश में वर्तमान में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना के अन्तर्गत केवल एक ही विद्यालय चलाया जा रहा है। मेरी सरकार के प्रस्ताव पर इस वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार से 3 अतिरिक्त विद्यालय स्थापित करने का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। यह विद्यालय जनजातीय क्षेत्र भरमौर, पांगी तथा लाहौल में 52 करोड़ रूपये की राशि से स्थापित किए जाएंगे।

52. तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को रोजगार पाने के योग्य बनाने की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में 3 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए। मेरी सरकार ने मार्च, 2018 से सितम्बर, 2018 के दौरान आई0टी0आई0 सोलन, नालागढ़, शाहपुर, शमशी, सुन्दरनगर तथा मण्डी में रोज़गार मेलों का आयोजन किया। इन मेलों में 127 कम्पनियों ने भाग लिया तथा 4 हज़ार 572 अभ्यार्थियों को रोज़गार के लिए चयनित किया गया।

53. मेरी सरकार ने चालू वित्त वर्ष में जिला मण्डी में एक क्लस्टर विश्वविद्यालय विधायी अधिनियम द्वारा स्थापित किया है। सरकार द्वारा प्रदेश में 'अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती' नामक योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत उन सभी विद्यार्थियों के नाम विद्यालय के गौरव पट्ट पर अंकित किए जा रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक जीवन में कुछ महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हो ताकि वे अपने विद्यालय के बच्चों को जीवन में दृढ़ता एवं विश्वास के साथ जीने के लिए प्रेरित करें। प्रदेश को भारत के अग्रणी मीडिया ग्रुप 'इंडिया टुडे' द्वारा शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का सम्मान प्रदान किया गया है।

54. चालू वित्त वर्ष में मेरी सरकार द्वारा सहायक आचार्य (कालेज) के 279 पद और कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 120 पद भरे गए। स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के 1251 पदों को पदोन्नति द्वारा भरा गया। इसके अतिरिक्त सभी श्रेणियों के 30 हज़ार वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, जिनमें 12 हज़ार वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट स्कूल प्रधानाचार्य के थे, को पूरा करके 2 हज़ार 435 स्कूल प्रधानाचार्य जिन्हें वर्ष 2008 से 2016 के दौरान तदर्थ या प्लेसमेंट आधार पर नियुक्त किया गया था, की पदोन्नति को चालू वित्त वर्ष के दौरान नियमित किया गया जिससे बड़ी संख्या में लम्बित मामलों का निपटारा हुआ।

55. चालू वित्त वर्ष में स्वास्थ्य विभाग में 359 चिकित्सकों व अन्य सहित कुल 823 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। 746 स्टाफ नर्सों के पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गई है। विभिन्न पैरा मैडिकल स्टाफ के 260 पदों का सृजन किया गया तथा 586 कर्मचारियों को नियमित किया गया।

56. मेरी सरकार प्रदेश में निःशुल्क दवाई नीति के अन्तर्गत जिला अस्पतालों में 330 दवाईयां, सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 216, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 106 तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों में 43 दवाईयां मुफ्त प्रदान कर रही है। राज्य के दूर–दराज़ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए किलाड़ (पांगी) में अक्तूबर, 2018 में टेलीमेडिसन की सुविधा शुरू की गई है।

57. यह हर्ष का विषय है कि राज्य में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान क्लीनिकों में लाई गई गर्भवती महिलाओं के उच्चतम अनुपात के लिए गैर ई0ए0जी0 राज्यों में हिमाचल प्रदेश ने पहला पुरस्कार प्राप्त किया है। इसी सूत्र पर चलते हुए, राज्य ने 'अटल आशीष योजना' के तहत बेबी किट प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है, ताकि कोई भी माँ और नवजात शिशु अच्छी देखभाल से वंचित न रहें।

58. मेरी सरकार ने सिविल अस्पताल आनी, थुरल, राजगढ़, तीसा और शाहपुर को 100 बिस्तर वाले अस्पतालों में स्तरोन्नत किया है, 100 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल करसोग को 150 बिस्तर वाले अस्पताल में, 50 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल नेरवा को 75 बिस्तर वाले अस्पताल में और नागरिक अस्पताल नूरपुर को 200 बिस्तर वाले अस्पताल में स्तरोन्नत किया है। चालू वित्त वर्ष में 4 उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं। 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सिविल अस्पताल में स्तरोन्नत किया गया है। इन नए खोले गए और स्तरोन्नत किए गए स्वास्थ्य संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 466 पदों का सृजन भी किया गया है।

59. राज्य ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को लागू करने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। राज्य में 'आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में लगभग 5 लाख परिवारों को प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जा रही है। शेष जनसंख्या की कवरेज के लिए राज्य में 'हिमकेयर योजना' जोकि 'आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के बराबर है, को प्रारम्भ किया है। इसके अन्तर्गत

2 लाख 75 हज़ार परिवारों को शामिल कर लिया गया है।

60. मेरी सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान गंभीर रूप से बीमार रोगियों की समस्याओं को दूर करने के लिए शिमला, ऊना, बिलासपुर, पालमपुर, हमीरपुर, चम्बा और पांवटा साहिब में 7 नई डायलेसिस इकाईयां स्थापित की हैं, यह मण्डी, सोलन, कुल्लू और धर्मशाला में मौजूद 4 डायलेसिस इकाईयों के अतिरिक्त है। नाहन और नूरपुर में डायलेसिस इकाईयां शीघ्र ही संचालित की जाएगी।

61. मेरी सरकार ने 24 मार्च, 2018 को 'मुख्य मन्त्री क्षय रोग निवारण योजना' का शुभारम्भ किया है। इस योजना के अन्तर्गत 'क्षय रोग मुक्त हिमाचल अभियान पखवाड़े 2019' का 1 जनवरी, 2019 से 15 जनवरी, 2019 तक 10 जिलों में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया जिसमें स्वास्थ्य टीम द्वारा कुल 364 नए क्षय रोगियों का उपचार किया गया।

62. मेरी सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में कुल 9 हजार 500 हैक्टेयर भूमि का पौधरोपण किया जा रहा है। विद्यार्थियों को वन व पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए 'विद्यार्थी वन मित्र योजना', वनों के प्रबन्धन में स्थानीय लोगों को सक्रिय रूप से जोड़ने के लिए 'सामुदायिक वन संवर्द्धन योजना' तथा जंगली जड़ी–बूटियों के संग्रह और निजी जमीन में इसके उत्पादन को बढ़ावा

देकर रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से 'वन समृद्धि–जन समृद्धि योजना' आरम्भ की गई है।

63. प्रदेश सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में जिला सिरमौर के तीन विकास खण्डों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीय अनुकूलन कोष के तहत 9 करोड़ 71 लाख की लागत से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्य किये गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण हेतु 'पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार योजना' का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत विशिष्ट कार्य करने वाले 15 व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने हेतु 7 लाख 50 हजार की नगद राशि व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है।

64. मेरी सरकार स्वच्छता को प्रोत्साहन देने के लिए विषेष ध्यान दे रही है तथा इसी क्रम में हाल ही में दो गड्ढे वाले शौचालयों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रदेष में स्वच्छता के कार्यक्रम को उत्कृष्ट ढंग से चलाने हेतु 20 करोड़ रूपये की राषि बतौर पुरस्कार दी गई है। राज्य ने ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए पंचायतों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विकसित की है। राज्य के प्रत्येक जिले में शहरी कस्बों के निकट 8 से 10 पंचायतों का समूह बनाकर कचरा प्रबंधन हेतु एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 12 जिलों की 120 ग्राम पंचायतों को पहले

चरण में शामिल किया गया है। कचरा प्रबंधन हेतु इस पहल में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत सरकार ने 120–150 पशुओं के लिए 50 घनमीटर क्षमता के 3 बायोगैस प्लाँट ऊना, सोलन तथा कांगड़ा जिलों में स्थापित किए हैं। 65. युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा प्रदान कर राष्ट्र निर्माण में इनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहें हैं। मेरी सरकार द्वारा खेल स्टेडियमों तथा खेल मैदानों के निर्माण के लिए 20 करोड़ 80 लाख रूपये खर्च किए जा रहे हैं। 'मुख्य मंत्री खेल विकास योजना' के अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक बड़ा खेल मैदान विकसित करने के लिए 6 करोड़ 80 लाख रूपये की राशि खर्च की जा रही है।

66. चालू वित्त वर्ष में 'राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन' के अन्तर्गत 240 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए। योजना के अन्तर्गत 730 लाभार्थियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण और 116 को रोजगार भी प्रदान किया गया। लघु उद्यम स्थापित करने के लिए 244 लाभार्थियों तथा 59 स्वयं सहायता समूहों को कम ब्याज पर ऋण सुविधा प्रदान की गई है।

67. चालू वित्त वर्ष में दिसम्बर, 2018 तक माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत प्रदेश को कुल 5 हजार 384 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कर अधिनियम, 1955 के

अन्तर्गत लोहा, स्टील, सभी प्रकार के यार्न व प्लास्टिक वस्तुओं पर लगने वाले कर में 25 प्रतिशत की कमी की गई है।

68. प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध जारी रखते हुए उनके हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया है। राज्य सरकार ने अपने नियमित कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2018 से देय 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किश्त जारी की और साथ ही राज्य में कार्यरत अनुबन्ध कर्मचारियों की ग्रेड पे में 25 प्रतिशत की वृद्धि भी की है। चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने पेंशनरों के हित में अनेक उल्लेखनीय निर्णय लिए हैं। प्रदेश सरकार ने श्रेणी–3 और श्रेणी–4 के कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया है कि उनके द्वारा दिनांक 12–06–2018 व इसके पश्चात् समय पूर्व ऐच्छिक सेवानिवृति लेने की दशा में, वे पूर्ण पेंशन के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा उन सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में पूर्ण पेंशन (दिनांक 05–07–2018 से) प्रदान की गई है जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन पर पेंशन की एवज़ में एक मुश्त राशि प्राप्त की थी।

69. प्रदेश सरकार ने अपने नियमित कर्मचारियों व पैंशनधारकों को 1 जुलाई 2018 से 4 प्रतिशत अन्तरिम राहत की किश्त जारी की है। मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी 210 रूपये से बढ़ाकर 225 रूपये तथा पार्ट टाईम वर्कर्ज़ की दिहाड़ी 26 रूपये 25 पैसे

से बढ़ाकर 28 रूपये 25 पैसे प्रति घण्टा की गई। राज्य सरकार ने चालकों का स्पेषल भत्ता 800 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये कर दिया है। वर्ष 2018–19 में कर्मचारियों, पैंशनरों, दिहाड़ीदारों व अन्य कर्मियों को लगभग 1 हजार 417 करोड़ रुपये के अतिरिक्त लाभ प्रदान किए गए।

70. मेरी सरकार ने वर्ष 2018–19 में कुशल व अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता पूर्ति के लिए 5 रोज़गार मेलों और 173 कैम्पस साक्षात्कारों का आयोजन किया जिसके माध्यम से 4 हज़ार 649 नियुक्तियाँ की गई।

71. मेरी सरकार ने एक वर्ष की इस अवधि में ईमानदार प्रयासों के साथ नई–नई योजनाएं आरम्भ की है तथा प्रदेश के विकास को गति प्रदान की है। सभी क्षेत्रों का समान विकास और सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित बनाने की दिशा में कारगर कदम उठाए हैं। विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसमें सबका सहयोग अपेक्षित होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब माननीय सदस्यगण निष्ठा एवं समर्पण से इस प्रदेश के लोगों की सेवा करते रहेंगे और सब मिलजुलकर प्रदेश को प्रगति के शिखर की ओर ले जाने में अपना भरपूर योगदान देंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ तथा आशा व्यक्त करता हूँ कि आप सब माननीय

सदस्यगण इस माननीय सदन में सार्थक चर्चा एवं विचार–विमर्श में बढ़–चढ़ कर भाग लेंगे।

जय हिन्द, जय हिमाचल।

***

Hon'ble Speaker and Hon'ble Members

1. I take this opportunity to extend a very warm welcome to all the Hon'ble Members to this fifth session of the thirteenth Himachal Pradesh Vidhan Sabha and the first session of the year, 2019. I would also like to convey my warm wishes for the New Year to all the Hon'ble Members of this August House and through you, to the people of the State. I am confident that this New Year will provide us strength and resolve to serve the people of the State.

2. My Government assumed office last year and the State got young leadership in the form of Chief Minister. This leadership demonstrated far-sightedness and energy by working in a planned manner. The grievances of the people were heard and redressed effectively by visiting each and every assembly constituency of the State and directly interacting with the people.

3. I am glad that my Government has followed the dictum of 'Sab Ka Sath Sabka Vikas' in letter and spirit as a guiding principle in all its endeavours by reframing policies and programmes. It is matter of pride that my Government, with the adoption of the ideal 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः' has fulfilled most of the election promises effectively in the first year of its tenure. I would provide necessary details of all achievements in my discussions hereinafter.

4. Agriculture makes a significant contribution to the State economy. It is a matter of great pleasure that in 2018-19 the Central Government hiked the Minimum Support Price of all notified Kharif and Rabi crops by at least 150 % of the cost of production. This initiative of the Union Government will help in doubling the income of the farmers. I am glad that my Government is adding new dimensions to the farming practices in the State. A new scheme namely 'Prakritik Kheti Khushaal Kisan' has been started by the State Government in the current financial year. Under this scheme, about 9,000 farmers were imparted training during the current financial year and about 3,000 farmers have successfully adopted this farming practice.

5. To ensure soil productivity by balancing nutrients, all farmers are being provided Soil Health Cards under 'Soil Health Card Scheme'. Till now 4,80,000 such Soil Health Cards have been prepared during the current financial year 2018-19. Subsidy has been increased for solar fencing under 'Mukhya Mantri Khet Sanrakshan Yojna' to protect crops from monkeys, wild and stray animals. A sum of Rs. 22 crore has been spent as subsidy under this scheme. In addition, 1,25,000 farmers have been covered under 'Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna' during 2018-19.

6. Horticulture is playing a significant role in the socio economic development of the State. Around 2,000 hectare

additional area has been brought under horticulture during the year 2018-19. Centrally sponsored schemes like 'Mission for Integrated Development of Horticulture', 'Rashtriya Krishi Vikas Yojna' and 'Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna' are playing a significant role in the development of horticulture in the State. During the current financial year, 35,500 square meter area has been brought under polyhouse, green house and 5,000 square meters under shade net houses and 2,000 square meter under plastic tunnel for protected cultivation of high value flowers and vegetables.

7. My Government has started 'Himachal Pushp Kranti Yojna' in the current financial year to provide employment opportunities to the rural youth through floriculture. 25,268 square meters area will be brought under polyhouses under this scheme. Likewise, my Government has also started 'Mukhya Mantri Madhu Vikas Yojna'. Beekeepers are being provided assistance under this scheme by providing Bee colonies, Bee hives and Bee keeping equipments.

8. To compensate for the loss incurred due to natural calamities in the horticulture sector, 1,62,000 horticulturists have been covered under 'Weather Based Crop Insurance Scheme'. A sum of Rs. 18.86 crore has been defrayed as subsidy on premium on 95.86 lac insured fruit plants under this scheme by

the State Government. In addition to this, for reducing cost, my Government has exempted apple, other fruits and vegetables from tax under Himachal Pradesh (Certain Goods Carried By Road) Act, 1999. From June, 2018, a reduction of 20% has been made in transportation rates of flowers by the Himachal Road Transport Corporation in its buses.

9. In order to uplift the financial condition of the farmers, the State Government has given a new direction to the activities being carried out in the cooperative sector. During the current financial year, my Government has launched Integrated Cooperative Development Projects in Solan and Mandi districts at a cost of Rs.163 crore which will strengthen the cooperative movement in these districts.

10. Live-stock also makes a significant contribution to the financial condition of the farmers. 2 new Veterinary Dispensaries have been opened and 8 Veterinary Dispensaries have been upgraded to Veterinary Hospital by my Government during the year 2018-19. An amount of Rs. 4.60 crore has been spent on providing 50% subsidy on feed to the indigenous pregnant cows reared by farmers belonging to Schedule Caste and other categories. Besides, the Government is providing subsidy to the beneficiaries of 'Dugdh Udyami Vikas Yojna' @ 20% on

purchase of indigenous breed of cow and 10% additional subsidy on purchase of other breeds of cow.

11. My Government has passed the Himachal Pradesh Go Vansh Sanrakshan and Samabardhan Bill, 2018 in the winter session for constitution of 'Go Sewa Aayog'. The main objective of constituting this Aayog is to help in preparing policies and action plans for protection, welfare and propagation of indigenous breeds of Cow in the State. With a view to providing shelter to the helpless Cows, Cow sanctuaries and big Go Sadans at District level are being established in the State. In addition, my Government has taken a significant decision that 15% of the total income of Temple Trusts will be provided as financial assistance towards management of Go Sadans and Go Shalas in the State.

12. With a view to improve financial condition of the farmers in the State, my Government has taken several significant decisions in implementation of 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme'. These decisions include prioritising water conservation and natural resource management works, assessment of 60:40 labour and material ratio at the district level, enhancing maximum number of permissible man days from 100 to 120 days, and releasing 10% State share in advance. An amount of Rs. 660 crore has been spent during the current financial year till December, 2018 under this scheme.

4,93,148 families have worked for 220 lac man days till now wherein 33,757 families have completed 120 man days. Out of these 63% man days are contributed by women.

13. In the current financial year, 15,873 land development related works have been carried out under MGNREGS which have increased the farmers income. Besides, 10,000 tanks having a water storage capacity of 8 crore litres have been constructed. For facilitating agriculture produce of the farmers being taken to the market, about 308 kilometres of rural roads have been constructed.

14. The assistance of Rs.1800/- being given to fishermen during the non-fishing season has been enhanced to Rs. 3000/- for 2,691 active reservoir fishermen. To help generating additional income to the farmers, my Government has provided financial assistance to the tune of Rs. 2.28 Crore under 'Neel Kranti Yojna' for construction of 100 new trout units.

15. My Government launched an ambitious programme named 'Jan Manch' for facilitating direct interface with the public for on the spot redressal of public grievances. Till January, 2019, 96 Jan Manch programmes have been organised in 63 Assembly Constituencies in which 24,424 demands and complaints were redressed. Through this programme, not only public grievances are redressed, but 246 health camps have also been organised in

which 38,178 people were medically checked. Besides, 4,578 mutations have been attested, 743 schemes were inspected, 28,225 various certificates were issued, documentations of 19,300 beneficiaries were completed, cleanliness campaigns were organised in 436 Gram Panchayats and 121 other places. 3.74 lac digital ration cards were issued and 1.42 lac Kisan Credit Cards were prepared and distributed during these Jan Manch programmes.

16. With a view to ensure transparency and accountability in governance and to provide corruption free administration to the public, my Government, through the use of information technology, has developed many IT enabled systems which are worth mentioning like Smagra Samadhan, Him Pragati, Jan Manch, Employment Generation and Online Applications for the registration of Cooperative Societies. Himachal Pradesh has become the first State in the Country which has achieved updation of Government Websites at the State level as well as all the districts in the State. Our softwares namely Manav Sampada, e-Vidhan and Mid Day Meal have been replicated by other States in the Country which is commendable. Himachal Pradesh has become a leading State in the Country to provide information through Mobile Apps like 'eBudget', 'mHimBhoomi', 'Circle rates', 'Shakti Mahila Surakha' and 'Shor Nahin' to its citizens. As

a result of these efforts, the State was awarded National e-Governance award for Manav Sampada and e-Vidhan and Web-Rattna award for Web portal during this financial year.

17. My Government has established Chief Minister IT cell to interact with the people of the State through social media. To enhance efficiency and accountability and to introduce paperless environment in the working of the Government Departments, e-Office has been introduced in 19 offices and 6,953 files are now being processed online. High speed internet facility has been provided to 221 Gram Panchayats in six Development Blocks of the State.

18. My Government has successfully transferred Rs. 3,175 crore to beneficiaries of 56 schemes through Aadhar enabled Bank Accounts under 'Direct Benefit Transfer Scheme'.

19. The State Government has developed 'Single Point of Contact' in 'Single Window System' in which 37 services of 10 Departments have been added to facilitate investors. As a result, investors can now get sanctions from all the concerned Departments for implementation of their projects without any interference through combined online applications.

20. My Government is strengthening rural governance through Panchayati Raj institutions. Towards this end, all Panchayats are now maintaining their accounts online in the

'Priya-Soft' software. All Parivar Registers have been made online with effect from 1st April, 2018.

21. My Government has completed digitisation of Musabies in Kangra, Bilaspur, Chamba, Kinnaur, Hamirpur, Lauhal & Spiti and Mandi districts under 'Digital India Land Records Modernization Programme'. After integrating Musabies with Jamabandies, this record has now been uploaded on the websites. The general public can download data pertaining to their Jamabandies along with Musabies.

22. On 23rd and 24th September, 2018, many tourists got stranded in Lahaul-Spiti district due to heavy rain and snowfall in Kullu, Chamba and Lahaul-Spiti districts. My Government swung into action immediately in this critical situation and promptly evacuated 252 people through 7 Indian Air force Helicopters. Apart from this, 2,509 people were evacuated by road through Rohtang Tunnel. 1,272 students, teachers and other people were also rescued from Holi Tehsil of Chamba district. Besides this, 120 persons, about 20,000 sheep and goats and 350 horses who got stranded due to unseasonal snowfall were also rescued from Bara Bhangal area of Kangra district. My Government expresses special gratitude to Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi for showing personal interest in providing help to save the lives of the stranded people.

23. My Government is committed to stop the drug menace. In this direction, a big campaign has been launched in the State. 1,342 cases have been registered under Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act in which 1,724 people including 10 foreigners have been arrested during this year. Regular campaigns are being organised to destroy the cultivation of Hemp and Opium. Thana level Drug prevention Committees have been constituted. Various campaigns are being run on social media platforms including Twitter and Facebook projecting celebrities to make youth aware of the vices of the Narcotic Drugs.

24. I am glad that my Government has established a coordination mechanism with neighbouring States' Chief Ministers and Director General of Police to completely eradicate this evil. On the initiative of the Chief Minister of Himachal Pradesh, a regional conference was held at Panchkula in which Chief Ministers of Haryana, Punjab and Uttrakhand and senior officers of Rajasthan, Delhi and Chandigarh participated. A decision was taken during this conference to set up a joint Secretariat for sharing intelligence and making a joint strategy for tackling the problem of Drug Mafia.

25. My Government has started 'Gudiya Helpline' and 'Shakti Button Mobile App' to counter crime against women.

1,398 complaints were received from January, 2018 till now in the Gudiya Helpline out of which 1,344 complaints have been disposed off. To combat eve teasers and other anti social elements and instill self confidence among girls to empower them, trainings are being imparted to girl students under 'Aatam Raksha' and 'Samager Siksha Abhiyan' in Government Schools during this year. About 54,000 girl students in 1,068 Schools have been trained by the State Police under this scheme. Three Women Police Stations have been set up in Solan, Hamirpur and Chamba districts in the current financial year.

26. My Government has also launched 'Hoshyiar Singh Helpline-1090' to curb corruption and to deal effectively with Van Mafia, Khanan Mafia and Drug Mafia in the State. Any person can give information on this toll free number about illicit felling of trees, drugs or mining activities. The identity of the informer is kept secret. 1,325 complaints have been received from January, 2018 till now in this Helpline and immediate action has been taken on all these complaints.

27. My Government is committed to stop illicit mining. With a view to check illegal mining of mineral products and to increase income of the State, 121 mines of sand gravel and stones situated along various Rivers and Nalas in the State have been

auctioned through an open auction. An amount of Rs. 405 crores will be received as royalty through this.

28. My Government has accorded a top priority to the construction and maintenance of roads. Due to the efforts of the State Government, the Government of India sanctioned Rs. 385 crore under 'Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna' till March, 2018 for construction of 120 roads and 4 bridges and Rs. 843 crore till December, 2018 for construction of 219 roads and 9 bridges. Apart from this, the State Government has sanctioned Rs. 3,676 crore for 1,359 MLA priorities to expedite the construction of roads and bridges. 948 projects have been completed till November, 2018.

29. My Government has forwarded an estimate of Rs. 3,000 crore to the Government of India for financial assistance from the World Bank for double lane up-gradation of National Highway 70 (New National Highway-3) from Hamirpur to Mandi having a length of 124 Kilometres and National Highway 72-B (New National Highway 707) from Paonta Sahib to Gumma having a length of 97 Kilometres.

30. Upholding the principle of 'Water is Life', my Government is committed to providing clean and safe drinking water to the people of the State. To achieve this objective, a target of providing water @ 70 Litres per person per day in

500 habitations was fixed during the current financial year. This facility has been provided to 289 habitations till November, 2018.

31. A drinking water crisis arose due to adverse weather conditions last year and was successfully tackled by my Government with efficient management. For improving water availability in Shimla city my Government has taken two important decisions whereby the work of providing 10 MLD additional water from Sutlej River at a place named Chaba has been started. A decision has also been taken to construct a Dam to maintain the level of water in Giri source of the Shimla Drinking Water Supply Scheme. In addition, 1,594 additional hand pumps have been installed in the drought prone and drinking water scarce areas in this financial year till now.

32. On 16th January, 2019, the World Bank has accorded its approval to Rs. 986 crore for Shimla Water Supply and Sewerage Project and has also given its consent to release the first instalment of Rs. 292 crore. To plug water leakage, the Shimla Water Management Corporation Limited has replaced the main water supply line of 14 KMs which has resulted in increase of water availability in Shimla town from 40 MLD to 51 MLD. In this process, the leakage of water has been reduced from 27% to less than 5% now. Main water supply lines from Cragnano to

Dhalli (7.5 KMs), Ashwani Khad to Kasumpti (4.5 KMs) and Sanjauli to Ridge storage tank (2 KMs) have been replaced.

33. My Government has provided irrigation facilities to 1,880 hectares land till November, 2018 under minor irrigation schemes. In addition, an amount of Rs. 42 crore has been released to accelerate the construction work of medium irrigation project, Nadaun which has resulted in early completion of this work on the right bank of the source.

34. My Government has generated 1,765 Million Units of electricity till December, 2018 in the current financial year which is 91% of the target for the year. 20,520 old electricity meters have been replaced with new electronic meters in various consumer premises and 4,325 old wooden polls existing in various HT&LT lines have been replaced with the iron polls in the current financial year.

35. 873 Kilowatt high capacity grid operated roof top and solar power plants have been set up at different places by my Government. To give it a further boost, the State Government has approved additional subsidy to the tune of 10% or Rs. 4,000 per Kilowatt out of the State exchequer to the domestic consumers. In addition, 139 Kilowatt capacity of high powered grid solar power plant; 5,953 solar street lights and solar water heating systems having a capacity of 5,000 litres per day; and one small

hydro electric project of 3.50 Megawatt capacity have been set up in the State during this financial year.

36. Transparent coaches (Vistadome) have been introduced on the Kalka-Shimla Railway track by the Government of India during the current financial year. This will increase tourist inflow to the State and showcase natural beauty of the State at National and International levels. Besides, the Nangal Dam-Talwara Railway Track has been opened for traffic with effect from January, 2019 from Amb-Indora to Daulatpur Chowk by completing the work. The extension of this Railway track up to Daulatpur Chowk will facilitate tourists to reach Chintpurni, Jawalaji and other tourist places.

37. My Government has accorded approval for acquisition of land measuring 25.21 hectares in the first phase of 20 Kilometres Bhanupalli-Bilaspur-Beri Railway track and the rest of the land acquisition work is in progress. The land falling in the State on the Nangal Dam-Talwara Railway Track has been acquired and process of registration and mutation for transferring this land in the name of Railways is in progress.

38. In order to promote rapid and balanced industrialisation in the State, approval for 113 Projects have been accorded by the 'Single Window Clearance and Monitoring Authority' during the tenure of my Government. These projects

contain investment proposals of Rs. 3,622 Crore with expected employment generation potential of 7,655 persons.

39. My Government has launched 'Him Pragati' online monitoring system wherein Multi Purpose Power Projects, Industrial Projects, Tourism Projects and other Infrastructure Projects are being monitored by the Chief Minister himself for quick approval and disposal. 79 Projects having an estimated investment of Rs. 10,202 Crore are being monitored through this system.

40. My Government has sanctioned Rs. 10 Crore for 30 entrepreneurs under the 'State Food Processing Mission'. My Government has launched 'Mukhya Mantri Swablamban Yojna' to promote entrepreneurship and self employment generation among youths in the State. Start-up scheme has been started in the State. Under the scheme, 8 centres have been set up in the State in which 40 Start ups have been registered and among these, 6 have started operation. The Government of India has recognised Himachal Pradesh ‘Start-up eco system’ as the 'Hill State Leader' and 'Aspiring Leader'. Himachal Pradesh has been rated as the 'Regulator Change Champion' for implementation of the Start-up scheme by the Government of India.

41. My Government has launched a scheme namely 'Nai Raahein, Nai Manzilein' with the aim to promote rural and

unexplored areas of the State from tourism point of view and to provide self employment opportunities for the youth. In the first phase of the scheme, tourism projects worth Rs. 50 crore are being implemented which include Eco Tourism Project at Janjehli of Mandi district, Para Gliding destination at Bir Biling of Kangra District, Ski destination at Chanshal of Shimla District, Larji Reservoirs of Kullu District and Pong Dam Reservoir of Kangra District. At present, the construction work of new Heliport and Helipads is in progress at Banredu, Sanjauli-Dhalli bye pass Shimla District, Chowari and Kundi of Chamba District, Khoshala Vashishth of Kullu District, Kunnu, Nachan, Deem Kataru and Kangni Dhar of Mandi District and Gompa of Lauhal & Spiti District. In addition to this, a site has been identified at Nagchala in Mandi District for setting up an International Airport.

42. My Government has provided direct benefit to 1.60 lacs eligible people under 'Social Security Pension Scheme' by reducing the age limit from 80 years to 70 years, without any income ceiling. Resultantly, 60,000 new people have become eligible for pension and the pensionary benefits in respect of another one lac people in the age group of 70 to 80 years have been increased. Besides, pension is being granted to 37,139 eligible persons of other categories too. An amount of Rs. 600

crore is being spent by the State Government for granting Social Security Pension to 5.11 lac people in the current financial year.

43. My Government is committed to the welfare of women and children. Financial assistance being provided under 'Mother Teresa Asahya Matri Sambal Yojna' has been enhanced from Rs. 4,000 to Rs. 5,000 per child per year during this financial year. Besides, grant provided under 'Beti Hai Anmol Yojna' on birth of a girl child belonging to BPL family has been enhanced from Rs.10,000 to Rs.12,000. It has benefited 21,483 persons.

44. Himachal Pradesh Saksham Gudia Board has been constituted by my Government. The main objective of the Board are to empower girls and adolescent girls, make recommendations on the Act, Rules, Policies and Programmes related to safety and protection of girls and adolescent girls along with reviewing implementation of various programmes run by different Departments for the upliftment and empowerment of the girls and make suggestions to prevent crimes against young girls.

45. Himachal Pradesh has been declared as the best performing State by the Government of India for achieving 147% target under the ‘Pradhan Mantri Maatri Vandana Yojna’. The State was also adjudged first in the country for successful implementation of ‘Pradhan Mantri Surakshit Matritav Abhiyan’.

46. My Government is providing subsidy to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the rate of Rs. 1.30 lac per beneficiary for the construction of new houses and Rs. 25,000 per beneficiary for repairs of the house. In the current financial year, an amount of Rs.18.36 crore is being spent to achieve the target for construction of 1,412 houses.

47. An amount of Rs. 21.87 crore has been released to the low and middle income class families under Pradhan Mantri Awas Yojna-Gramin for construction of houses in the current financial year. The construction work on 3,158 has been completed whereas work on 777 houses is in progress. In September, 2018, the Government of India has awarded first prize to the State for outstanding work under this scheme. Besides, under 'Mukhyamantri Awas Yojna', 3,014 houses are being constructed with a cost of Rs. 42 crore during the year 2018-19.

48. My Government has given top priority for the welfare of Ex-servicemen, serving soldiers, widows, war widows, gallantry award winners and their dependents of the State. Monthly pension in respect of Ex-servicemen and their widows who were getting pension @ Rs. 500 per month, has been enhanced to Rs. 3,000 per month. The income limit for granting scholarship to the children of Ex-servicemen and soldier's

widows from special fund, has been enhanced from Rs. 3 lac to Rs. 7 lac per year. Rs. 10.55 crore has been disbursed by my Government to those 1,682 Ex-servicemen or their widows aging 60 years and above who are not getting any kind of pension, 934 gallantry award winners, 35 dependents of war martyrs, disabled soldiers and 54 eligible non-pensioner Ex-Servicemen or their widows in the current financial year. Besides, an amount of Rs. 60 lac has been disbursed for relief and rehabilitation of Ex-Servicemen.

49. My Government decided to purchase pulses through Buffer-Stocks which has resulted savings in expenditure in the current financial year. One Kilogram additional dal chana is being provided to the ration-card holders under special subsidised scheme. As a result of transparency in purchase of pulses, an amount of Rs. 51.73 crore has been saved from February, 2018 till October, 2018. Besides, sugar is being purchased from Co-operative Mills of Haryana State. In this way, my Government has saved Rs. 89.18 crore in total on purchase of pulses and sugar in the current financial year. Due to this saving in expenditure a reduction of Rs. 5 per Kilogram in price of sugar for all ration-card holders has been provided.

50. Government of India has launched an ambitious scheme namely 'Ujjwala Yojna' for environmental protection and

women empowerment under which gas connections are being provided to housewives. Till now, 86,000 connections have been issued under this scheme. As a sequel to it, my Government has launched 'Grihini Suvidha Yojna' in the State under which totally free gas connections are being issued to all the eligible housewives. Till 31st January, 2019, free gas connections have been issued to 40,000 families and this process will continue till gas connections are provided to all the eligible families.

51. My Government is committed to over-all development of Scheduled Tribes and Scheduled Tribal areas. An amount of Rs. 567 Crore is being spent in the current financial year under Tribal Sub-Plan in various Scheduled Tribe Areas. In addition to this, Rs. 43 crore has been released by the Government of India under Special Central Assistance to the State in the current financial year. Approval for an additional amount of Rs. 67.70 crore has been accorded. This amount is the highest ever in comparison to the additional amount sanctioned by the Government of India in any financial year. Presently, only one school is being run under Eklavya Aadarsh Awasiya Vidyalya Yojna in the State. On the proposal sent by my Government, the Central Government has sanctioned 3 additional Schools in the current financial year. These schools will be set up in the tribal

areas of Bharmour, Pangi and Lahaul with an amount of Rs. 52 crore.

52. Through Technical Education and Skill Development, special efforts are being made in the direction of making youth of the State eligible for employment. 3 new Industrial Training Institutions have been opened in the current financial year. Job fairs were organised during March, 2018 to September, 2018 at ITI Solan, Nalagarh, Shahpur, Shamshi, Sundernagar and Mandi by my Government. 4,572 candidates were selected for jobs by 127 Companies which participated in these fairs.

53. A Cluster University has been established by my Government by Legislative enactment in District Mandi, during the current financial year. A scheme namely 'Akhand Shiksha Jyoti, Mere School se Nikle Moti' has been launched by the State Government. Under this scheme, names of all those students who have achieved exemplary position in social life are being entered on the School honour boards so as to inspire the students of their Schools to inculcate determination and confidence in their lives. 'India Today', the leading media group in India, has honoured the State for best performance in the field of education.

54. My Government has filled up 279 posts of Assistant Professors (Colleges) and 120 posts of Junior Office Assistants during this financial year. 1,251 posts of various categories were

filled up by promotion in the School cadre. Besides, to expedite pending promotions, 30,000 Annual Confidential Reports including 12,000 of Principals were completed. 2,435 School Principals who were earlier appointed on placement basis between 2008-16 were appointed on regular basis, resulting in settling a large number of pending cases.

55. 359 Doctors along with other staff total numbering 823 employees were appointed in the Health Department during the current financial year. Approval of filling up 746 posts of Staff Nurses was accorded. 260 posts of various Paramedical staff were created and 586 employees were regularised.

56. My Government is providing 330 medicines in District Hospitals, 216 in Civil Hospitals and Community Health Centres, 106 in Primary Health Centres and 43 in Health Sub Centres free of cost under free medicine policy. Telemedicine facility has been started at Killar (Pangi) in October, 2018, to strengthen health facilities in the far-flung areas of the State.

57. It is a matter of pleasure that Himachal Pradesh has bagged first prize among Non-EAG States for the highest proportion of pregnant women brought to the Pradhan Mantri Surakshit Matritava Abhiyan Clinics in the State. Continuing on the same analogy, the State has launched a scheme to provide

baby kits under the 'Atal Ashish Yojna' so that no mother and new borne is deprived of good care.

58. My Government has upgraded Civil Hospitals: Aani, Thural, Rajgarh, Tissa and Shahpur to 100 bedded Hospitals; 100 bedded Civil Hospital Karsog to 150 bedded Hospital; 50 bedded Civil Hospital Nerwa to 75 bedded Hospital; and Civil Hospital Nurpur to 200 bedded Hospital. 4 Health Sub Centres and 8 Primary Health Centres were opened during the current financial year. 5 Primary Health Centres were upgraded to Community Health Centres and 5 Community Health Centres were upgraded to Civil Hospitals. 466 posts of various categories were created for these newly opened and upgraded Health Institutions.

59. The State has taken a big leap forward in the direction of implementing ‘Universal Health Coverage’. 'Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna' is being run successfully in the State. Under this scheme, free treatment facility up to 5 lac per family per year is being provided to around 5 lac families through the empanelled Hospitals. For covering the left out population, ‘Him Care Scheme’ which is at par with Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojna; has been launched under which 2.75 lac families have been covered.

60. In order to mitigate the hardships being faced by seriously ill patients, my Government has opened 7 new dialysis units at Shimla, Una, Bilaspur, Palampur, Hamirpur, Chamba and Poanta Sahib. These are in addition to the existing 4 dialysis centres at Mandi, Solan, Kullu and Dharamshala. Dialysis units at Nahan and Nurpur will be operationalized shortly.

61. My Government has launched 'Mukhyamantri Kshay Rog Niwaran Yojna' with effect from 24th March, 2018. Under this scheme, 'Kshay Rog Mukt Himachal Abhiyan Pakhwara 2019' was conducted successfully in 10 Districts from 1st January, 2019 to 15th January, 2019. 364 new T.B. patients were treated by the Health Department during this fortnight.

62. My Government has taken up plantation work in 9,500 hectare land during the current financial year. To make students aware concerns in Forest and Environmental protection, 'Vidhyarthi Van Mitra Yojna' has been launched. Similarly to involve the local community in forest management, 'Samudayik Van Sambarhdan Yojna' has been launched. Further, to generate employment opportunity by collecting wild herbs through encouraging its production in the private land 'Van Samridhi Jan Samridhi Yojna' has been launched.

63. In the current financial year, the State Government has undertaken climate change adaptation work at a cost of Rs. 9.71 crore under National Adaptation Fund in the drought prone areas of 3 development blocks of the Sirmour District. Besides, 'Paryavaran Netritav Purskar Yojna' has been launched for environmental protection in the State. For doing outstanding work, 15 persons have been rewarded with a cash prize of Rs.7.50 lac and a citation under the scheme.

64. My Government is paying special attention to encouraging cleanliness and towards this end a twin pit toilet scheme has been recently launched. The State was awarded a cash prize of Rs. 20 crore for doing excellent work under the sanitation programme. The State has developed a protocol for solid and liquid waste management for adoption by the Panchayats. A new initiative has been started for waste management in all the Districts of the State by taking up a cluster of 8 to 10 Panchayats adjourning the urban areas. In the first phase, 120 Panchayats have been included in the initiative. The Government has set up three bio-gas plants having a capacity of 50 cubic meters each for 120-150 cattle in Una, Solan and Kangra Districts for animal waste management.

65. Special efforts are being made to ensure active participation of youth in nation building by channelizing their

energy into the right direction. An amount of Rs. 20.80 crore is being spent by the Government for construction of Stadiums and Play Grounds. An amount of Rs. 6.80 Crore is being spent on the development of one big play ground in each assembly constituency under 'Mukhyamantri Khel Vikas Yojna'.

66. Under National Urban Livelihood Mission, 240 Self Help Groups were formed during the current financial year. Under this scheme, training in different trades was imparted to 730 beneficiaries of which 116 were provided employment. Low interest loan facility has been provided to 59 Self Help Groups and 244 beneficiaries for setting up small ventures.

67. The State has received a sum of Rs. 5,384 crore under Goods and Services Tax till December, 2018, in the current financial year. Under the Himachal Pradesh Passenger and Goods Tax Act, 1955, a 25% reduction has been given on taxes levied on Iron, Steel and all types of Yarn and Plastic articles.

68. Continuing the maintenance of cordial relationship with employees, the State Government has ensured the protection of their interests. The State Government has released 3% additional dearness allowance to its regular employees due with effect from 1st January, 2018 and has simultaneously made an increase of 25% in the Grade Pay of the contractual employees

working in the State. The State Government has taken many important decisions in the interest of pensioners during the current financial year. A decision has been taken in respect of class-III and IV employees which entitles them to full pension in the event of seeking pre-mature retirement on or after 12.06.2018. Besides, full pensionary benefits have been granted with effect from 05.07.2018 to the employees who had received a lump-sum amount in lieu of pension on their absorption in the Public Sector Undertakings.

69. The State Government has released an instalment of 4% interim relief to its regular employees and pensioners with effect from 1st July, 2018. The minimum wage rate of daily wage workers has been enhanced from Rs. 210 to Rs. 225 and part time hourly wages have been enhanced from Rs. 26.25 paisa to Rs. 28.25 paisa. The State Government has increased the special allowance paid to the Drivers from Rs. 800 to Rs. 1000. Benefits totalling to about Rs. 1417 crore have been extended to employees, pensioners, daily waged and other workers.

70. My Government organised 5 job fairs and 173 campus interviews during the current financial year to provide employment opportunities to the skilled and unskilled labourers and 4,649 appointments were made.

71. During this period of one year my Government has launched different new schemes in the right earnest and has accelerated the pace of development. Effective steps have been taken in the direction of ensuring balanced development of all areas and towards welfare of all classes. Development is a continuous process in which contribution of all is solicited. I am fully confident that all the Hon'ble Members will serve the people of the State with utmost dedication and sincerity and all will contribute to bringing the State to the top of the development ladder. I, once again, extend New Year wishes to all of you and hope that all the Hon'ble Members will actively participate in the debate and discussions in this August House.

Jai Hind, Jai Himachal.

***